पड़ताल सखी सेंटर में 2,349 महिलाओं ने न्याय की गुहार, चारदीवारी में भी सुरक्षित नहीं नारी

अपनों के ही जुल्म की शिकार हुई 2080 महिलाएं

अजहर खान

नवभारत, जबलपुर। घर की चारदीवारी के भीतर संस्कारधानी की महिलाएं आज भी सबसे असुरक्षित हैं। सखी सेंटर में बीते डेढ़ साल में 18 महीनों के अंदर जनवरी 2025 से 30 जून 2026 तक कुल 2,349 पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई हैं इनमें से अकेले 2,080 मामले घरेलू हिंसा के हैं मतलब महिलाएं अपनों के जुल्म का ही शिकार हो रही। यह आंकड़े न केवल बेहद चौंकाने वाले है बल्कि संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके पारिवारिक परिवेश को लेकर चिंताजनक और कड़वी हकीकत बयां कर रहे है कि सुरक्षा का दम भरने वाले परिवारों के बंद कमरों के पीछे महिलाओं पर किस कदर मानसिक और शारीरिक जुल्म ढहाया जा रहा है

नवभारत को पड़ताल के दौरान जबलपुर के वन स्टॉप सेंटर (सखी) के प्रशासनिक रिपोर्ट के आंकड़े केवल एक सरकारी टेबल की सांख्यिकी नहीं हैं, बल्कि यह समाज की उस सोच पर करारा तमाचा भी है जो महिलाओं को पूजनीय तो कहती है, लेकिन बंद कमरों में उन्हें प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहा है। यह साफ गवाही दे रहे है कि महिलाएं बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने ही घरों में असुरक्षित हैं। अब जरूरत केवल कानूनी कार्रवाई की नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और घरेलू संस्कारों को बदलने की भी है।

प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर (सखी) जबलपुर कार्यालय में दर्ज मामले

घरेलू हिंसा	-	2080
बाल विवाह	-	2
बाल यौन शोषण	-	1
बलात्कार	-	13
दहेज उत्पीड़ना	-	5
किसी अन्य प्रकरण का अपराध	-	1
गुमशुदगी अपहरण	-	49
साइबर अपराध	-	16
अनाथ	-	1
अन्य	-	131
छेड़छाड़	-	9
लिव इन रिलेशन	-	41
कुल	-	**2349**

1 जनवरी 2025 से 30 जून 2026 तक के आंकड़े

घर बन रहे नरक : हर 10 में से 9 महिलाएं प्रताड़ित

सखी सेंटर में दर्ज यह आंकड़े समाज का कड़वा सच बयां करने वाला आईना है। कुल मामलों में से 88.5 प्रतिशत हिस्सेदारी सिर्फ घरेलू हिंसा की है। जिन हाथों पर सुरक्षा का भरोसा था, वही हाथ प्रताड़ना दे रहे हैं। ये आंकड़े महिला सुरक्षा अभियानों की जमीनी हकीकत को भी बयां कर रहे है। साथ ही यह आंकड़े यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि तमाम कड़े कानूनों और जागरूकता अभियानों के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी संवेदनशील बनी हुई है?

जुल्म पर उठती आवाज, सुलह से भर रही रिश्तों की दरार

इन डरावने आंकड़ों के बीच राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अब महिलाएं जुल्म को किस्मत मानकर चुप बैठने वाली नहीं हैं। वन स्टॉप सेंटर (सखी) की चौखट पर पहुंच रही मामले सबूत है कि महिलाएं अब थानों के चक्कर काटने के बजाय एक ही छत के नीचे कानूनी, मेडिकल और मानसिक मदद की ताकत को पहचान चुकी हैं जहां कार्रवाई के साथ आधे मामले तो सुलह से ही निपट रहे है और रिश्तों में आई दरार भी भर रही है लेकिन महिला हिंसा के बढ़ते मामले बेहद चिंताजनक है कि आखिर कब तक बेटियां और महिलाएं अपनों के ही हाथों इस तरह लहूलुहान और प्रताड़ित होती रहेंगी।

दरिंदगी, ब्लैकमेलिंग, दहेज उत्पीड़ना का शिकार

18 महीनों में महिलाएं साइबर, ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी का भी शिकार होकर सखी सेंटर पहुंचीं है। समाज की दरिंदगी का आलम यह है कि इस अवधि में बलात्कार, दहेज उत्पीड़न के मामले भी पहुंचे। इतना ही नहीं बाल विवाह और बाल यौन शोषण के मामले यह बताने के लिए काफी है कि बच्चों का बचपन निगलने वाले भेड़िए इसी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर सितम ढाहाया जा रहा है इसके अलावा महिलाएं साइबर क्राइम ब्लैकमेलिंग, अश्लीलता का भी शिकार हुईं। गुमशुदगी और अपहरण से लेकर बेसहारा छोड़ी गई महिलाओं से लेकर अनाथ बच्चे की मौजूदगी यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर हमारा सामाजिक ताना-बाना किस दिशा में जा रहा है?

इनका कहना है

हर मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाता है। घरेलू हिंसा में पहली प्राथमिकता परिवार को टूटने से बचाने औरकाउंसलिंग के जरिए आपसी समझाइश की होती है। 50 प्रतिशत मामलों में समझौते हो रहे है जबकि 40 ऐसे मामले है जो कोर्ट भेजे जा रहे है। 10 प्रतिशत मामलों में महिलाएं शिकायत करने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है।

गायत्री दीक्षित, वन स्टॉप सेंटर, अधिकारी

विजयवर्गीय इंदौर की उपेक्षा से आहत हैं तो महाकौशल में बगावत होनी चाहिए : तन्खा

जबलपुर। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को कथित तौर पर लिखे गए पत्र को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि यदि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की उपेक्षा से आहत हैं, तो जबलपुर और पूरे महाकौशल क्षेत्र में तो बगावत की स्थिति होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जबलपुर की लगातार अनदेखी की गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का विभाजन कर दिया गया, एमपीईबी का बड़ा हिस्सा जबलपुर से बाहर कर दिया गया, मनेरी औद्योगिक क्षेत्र आज तक विकसित नहीं हो सका, डिफेंस फैक्ट्रियां बदहाल हैं और क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं बन पाया। जबलपुर में प्रस्तावित डिफेंस क्लस्टर का कोई अता-पता नहीं है। शहर की करीब तीन लाख महिलाएं सिलाई और वस्त्र कारोबार से जुड़ी हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा बाजार विकसित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ।

पिछले 30-40 वर्षों में कोई बड़ा उद्योग नहीं आया और हवाई सेवाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। मुख्यमंत्री को लिखे गए कथित पत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों में हो रही देरी और उपेक्षा का मुद्दा उठाया है। इंदौर के साथ हो रही अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि वे आहत हैं और पिछले ढाई सालों में उन्हें केवल असहयोग, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्होंने मास्टर प्लान के लंबित रहने, सिंहस्थ से जुड़े कार्य इंदौर में नहीं होने, एयरपोर्ट विस्तार सहित अन्य विकास परियोजनाओं में पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई।

कांग्रेस को विकास की बात करने का अधिकार नहीं : मंत्री

विकास के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी भी नेता को महाकौशल या जबलपुर के विकास की बात करने का अधिकार नहीं है क्योंकि जबलपुर सहित पुरे महाकौशल की उपेक्षा कभी हुई है तो वह कांग्रेस की सरकार के समय ही हुई है और जबलपुर सहित सम्पूर्ण महाकौशल को विकास की जो सौगाते मिली है, जो उपलब्धियां मिली है वह भाजपा के शासन में ही मिली है, यह बात लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मानस भवन जबलपुर में कही। आगे उन्होंने कहा कि जबलपुर में हुए विकास के उदाहरण तो प्रदेश और देश के दिए जाते है, जो भाजपा की सरकार में ही हुए है, और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में एक के बाद एक सौगाते जबलपुर को मिल रही है, जबलपुर में हुए विकास कार्यों को सब जानते है राजनीति अपनी जगह है लेकिन राजनीति की आड़ में विकास कार्यों की उपेक्षा हुई है इस तरह की चर्चा करना उचित नहीं है क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, हिसाब सभी से लिया जायेगा कि किसने जबलपुर के विकास के लिए क्या किया है।

यूनिफॉर्म के नाम पर मनमानी बर्दाश्त नहीं

जबलपुर। महिला होम साइंस कॉलेज में नई यूनिफॉर्म लागू किए जाने के विरोध में छात्राओं और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और जिले के उच्च शिक्षा अधिकारी अल्पेश चतुर्वेदी को महाकौशल कॉलेज पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कॉलेज प्रशासन पर बिना पूर्व सहमति नई यूनिफॉर्म लागू कर छात्राओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया गया। अभिभावकों का कहना है कि पहले से निर्धारित यूनिफॉर्म होने के बावजूद अचानक नई ड्रेस लागू करने का निर्णय उचित नहीं है। उनका आरोप है कि इस फैसले से हजारों परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने यूनिफॉर्म बदलने की प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में नई यूनिफॉर्म का निर्णय तत्काल वापस लेने, पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि छात्र-हितों की अनदेखी की गई है, इसलिए मामले की जांच पूरी होने तक प्राचार्य के विरुद्ध भी उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

तुलाराम चौक में पुलिस की छापेमारी, 592 जोड़ी माल जब्त

नामचीन ब्रांड के नाम पर नकली चप्पल बेचने वाले पकड़ाए

नवभारत, जबलपुर। कोतवाली पुलिस ने एक नामी ब्रांड कंपनी के नाम पर हूबहू दिखने वाली नकली चप्पलें बेचने वाले दो बड़े थोक व्यापारी को रंगे हाथों दबोचा है। पुलिस ने दोनों दुकानों से कुल 592 जोड़ी नकली स्लाईडर्स जब्त की हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 1,77,600 रुपये आंकी गई है।कोतवाली थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली स्थित एल्यूडिकेशन एडवोकेट एण्ड सॉलिसिटर्स लॉ फार्म के जांच अधिकारी मयंक शर्मा निवासी सावरिया नगर, इंदौर ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत

दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि कोतवाली क्षेत्र की कुछ दुकानों पर ब्रांडेड पूमा कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर नकली चप्पलें बेची जा रही हैं। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुलाराम चौक स्थित मैडम फुटवेयर लेडिस फैंसी चप्पल एवं फुटवेयर के होलसेल काउंटर पर दबिश दी। दुकान की तलाशी लेने पर अंदर से पूमा कंपनी की हूबहू दिखने वाली 284 जोड़ी नकली स्लाईडर्स बरामद हुईं। पुलिस ने मौके से दुकान मालिक पंकज खत्री 33 वर्ष, निवासी घमापुर चौक को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई जामा मस्जिद के पीछे, अंधेरदेव स्थित आर.के. फुटवेयर शॉप नंबर 226 पर की गई। इस होलसेल दुकान के अंदर से पुलिस को 308 जोड़ी नकली स्लाईडर्स मिलीं। पुलिस ने यहाँ से दुकान मालिक आवेद अली 50 वर्ष, निवासी रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, आनंद नगर, गोहलपुर को हिरासत में लिया। दोनों थोक विक्रेताओं के पास से जब्त की गई चप्पलों की कुल संख्या 592 जोड़ी है।

ट्रांसफार्मर के खुले तारों में दौड़ रहे करंट ने ली युवक की जान, खेत में मिला शव

नवभारत,जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत परासिया में ट्रांसफार्मर के खुले तारों में दौड़ रहे करंट ने युवक की जान ले ली।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, परासिया निवासी राजकुमार उइके (40) ने सूचना दी कि उनका बेटा नरेश उइके (18) गांव के ही नरेश पटेल के खेत की तरफ शौच के लिए गया था। जब वह घर नहीं लौटा, तो चिंतित परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। ढूंढते हुए जब परिजन नरेश पटेल के खेत में पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। नरेश वहां बेसुध मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। खेत के पास ही बिजली विभाग का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे बिजली के खंभे तक खुले तार जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि नरेश का शरीर इन तारों से छू गया। करंट इतना जोरदार था कि नरेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के गर्दन के पास, कान के पीछे, पैर के पंजे और दोनों पैरों की पिंडलियों पर बिजली से झुलसने के निशान मिले हैं। बेटे की मौत से राजकुमार उइके के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एक नजर में

जीआरपी की सतर्कता से मोबाइल चोर गिरफ्तार

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं चोरी की संपत्ति की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जीआरपी जबलपुर द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। महिला प्रधान आरक्षक एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस स्टाफ को प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने कब्जे में चोरी का लैपटॉप एवं मोबाइल लेकर प्लेटफॉर्म के इटारसी छोर पर बैठा हुआ है। सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल पुलिस टीम एवं ड्यूटी पर उपस्थित आरपीएफ स्टाफ के सहयोग से मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे तत्परता से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रूपेश विश्वकर्मा उर्फ गोलू पिता कमल विश्वकर्मा 31 वर्ष निवासी इंद्रानगर गल्ला मंडी के पीछे थाना कुठला कटनी बताया गया तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक बैग मिला जिसमे लैपटॉप चार्जर सहित कीमत लगभग 60,000 और एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 7,000 के आसपास बताई गई, बरामद किया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

डॉ. नवीन कोठारी किए गए सम्मानित

जबलपुर, नवभारत। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित चिकित्सक दिवस तथा केंद्रीय शासन स्वास्थ्य योजना स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर डॉ. नवीन कोठारी को उनके उत्कृष्ट जनस्वास्थ्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉ. नवीन कोठारी को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन, विभाग के समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उत्कृष्ट संचालन, कुशल प्रशासनिक नेतृत्व तथा जनस्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय योगदान के लिए स्मृति-चिह्न एवं सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. नवीन कोठारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है तथा आमजन को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अतिथियों ने डॉ. नवीन कोठारी के समर्पण, सेवा-भाव, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ व्यक्त कीं। समारोह में सांसद आशीष दुबे एवं विधायक अभिलाष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे), केंद्रीय शासन स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के वरिष्ठ अधिकारी एवं अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

डेढ़ साल बाद भी नदी में डूबकर लापता किशोर का सुराग नहीं

हाईकोर्ट ने पिता के वकील को अंतिम पक्ष रखने का अवसर दिया

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सिंगरौली के 14 वर्षीय किशोर के सोम नदी में कथित रूप से डूबने के करीब डेढ़ वर्ष बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने के मामले को गंभीरता से लिया। सिंगरौली निवासी मनोज कुमार पनिका की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपना पक्ष विस्तार से रखने का अवसर दिया है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।

दरअसल कोर्ट के समक्ष पुलिस ने अब तक चार स्टेटस रिपोर्ट और 35 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें बताया गया कि एसडीआरएफ की तरह आरडीआरएफ की टीम भी नदी में व्यापक तलाश के बावजूद किशोर का पता नहीं लगा सकी। न्यायालय के पूर्व निर्देश पर किशोर के साथ गए दोस्तों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई, जिसकी रिपोर्ट रिकार्ड पर है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस की ताजा स्टेटस रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता की ओर से अभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। जिस पर न्यायालय ने अंतिम बहस के लिए समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

एसबीसी चुनाव : भदौरिया और गौरव मिश्रा ने बनाई बढ़त

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन-2026 की मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मुकाबला भी उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक की गिनती में राकेश सिंह भदौरिया, गौरव मिश्रा, जितेन्द्र कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शुक्ला और डॉ. विजय कुमार चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि महिला वर्ग में प्रतीका पाठक सबसे आगे चल रही हैं। जिला ग्वालियर, हरदा और होशंगाबाद की मतपेटियों की गिनती का एक चरण बुधवार को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। नर्मदापुरम जिले की तहसीलों की मतगणना गुरुवार को होगी, जबकि इंदौर की मतपेटियों की गिनती भी शुरू होगी। मतगणना के हर चरण में प्रत्याशियों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी हुई है। महिला प्रत्याशियों ने भी मुकाबले को रोचक बना दिया है। प्रतीका पाठक के साथ अब्बू पटेल, राजकुमारी शर्मा, गायत्री सुर्वे और रश्मि ऋतु जैन भी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी दौड़ में बनी हुई हैं। इससे अधिवक्ता समुदाय में महिला नेतृत्व की बढ़ती भागीदारी भी साफ दिखाई दे रही है। 16 जून से जारी मतगणना में अब तक 21,304 मतपत्रों की गणना हो चुकी है। इनमें 20,514 मत वैध पाए गए, जबकि 790 मतपत्र नियमों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त कर दिए गए।

साकेत जैन ने जिला कोषालय अधिकारी का पदभार ग्रहण किया

जबलपुर। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार साकेत जैन ने आज बुधवार को जिला कोषालय अधिकारी जबलपुर का पदभार ग्रहण किया। इसके पहले जैन डिंडौरी में जिला पेंशन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। राज्य शासन द्वारा उन्हें वरिष्ठ कोषालय अधिकारी सुश्री विनायिका लकरा के स्थान पर पदस्थ किया गया है। सुश्री लकरा को शासन द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

एएसआई के निलंबन पर अंतरिम रोक

आरोप पत्र देरी पर हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सिवनी पुलिस लाईन में पदस्थ एएसआई भारती चौबे के निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

एकलपीठ ने यह राहत देते हुए निर्देशित किया है कि यदि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर वैधानिक अपील प्रस्तुत करती हैं तो सक्षम अपीलीय प्राधिकारी 45 दिनों के भीतर उसका निर्णय करेगा। तब तक निलंबन प्रभावी नहीं रहेगा।

दरअसल भारती चौबे पर आरोप है कि उन्होंने रक्षित केंद्र सिवनी में पदस्थ रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर एक पीड़िता को शासकीय आवास बुलाया और विवाह कराने में मध्यस्थता कर सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर रायजादा ने दलील दी कि नौ फरवरी 2026 के निलंबन के बाद निर्धारित अवधि में आरोपपत्र जारी नहीं किया गया, जिससे निलंबन की वैधता प्रभावित होती है। इसके समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के अजय कुमार चौधरी निर्णय का भी हवाला दिया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश दिया।

ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग में 12 प्रतिशत का उछाल

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल द्वारा ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही वाणिज्य एवं परिचालन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मंडलों में माल ढुलाई बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप जून 2026 के दौरान पश्चिम मध्य रेल ने 5.45 मिलियन टन ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग दर्ज की। यह उपलब्धि गत वर्ष के इसी माह में की गई 4.85 मिलियन टन लोडिंग की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक माल ढुलाई में कुल 15.31 मिलियन टन ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग दर्ज हुई है। यह उपलब्धि गत वर्ष के तीन माह में की गई 14.40 मिलियन टन लोडिंग की तुलना में 6.3 प्रतिशत अधिक है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि महाप्रबंधक के सतत मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के साथ-साथ वाणिज्य और परिचालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जबलपुर, भोपाल तथा कोटा मंडलों में किए गए समर्पित और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को ज्ञापन से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रहितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे एनएसयूआई के प्रभारी अचल नाथ सहित कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद संगठन ने पुलिस पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन और छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

एनएसयूआई के अनुसार संगठन शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री के समक्ष छात्रहितों से जुड़े मुद्दे उठाने जा रहा था। प्रस्तावित ज्ञापन में बी.पी.एड. विभाग की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, छात्रवृत्ति से जुड़ी लंबित समस्याओं का निराकरण तथा छात्रा निकिता रजक द्वारा की गई शिकायत की निष्पक्ष जांच की मांग प्रमुख रूप से शामिल थी। एनएसयूआई प्रभारी अचल नाथ ने कहा की ज्ञापन सौंपने से पहले ही पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

लापरवाही सकरी हुई राह, आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है

पेवर ब्लॉक बिछाने के बाद सड़क पर छोड़ा मलबा

जबलपुर, नवभारत। इन दिनों नेपियर टाउन से शास्त्री पुल की ओर जाने वाले मार्ग में पेवर ब्लॉक लगाने के कार्यों के बाद निर्माण एजेंसी की लापरवाही आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। सड़क किनारे पेवर ब्लॉक बिछाने के बाद निर्माण सामग्री और मलबा हटाया ही नहीं गया, जिससे सड़कें पहले की तुलना में काफी सकरी हो गई हैं। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है और वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। वही बारिश के शुरू होते ही सड़क किनारे पड़ा मलबा पानी के साथ बहकर सड़क पर फैल रहा है। इससे फिसलन बढ़ गई है और दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। कई जगह नालियां भी मलबे से पट रही हैं, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है और जलभराव की स्थिति बन रही है।

तत्काल हटाया जाए मलबा

सड़क से गुज़रने वाले लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एजेंसी को तत्काल मलबा हटाकर सड़क को पूरी तरह साफ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे आमने-सामने आने वाले वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है और जाम जैसी स्थिति बन जाती है रहवासियों ने नगर निगम से मांग की है कि निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए और सड़कों पर छोड़े गए मलबे को तत्काल हटाया जाए। लोगों का कहना है कि विकास कार्य तभी सार्थक होंगे, जब उनके बाद नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन भी सुनिश्चित किया जाए।